why one has to go into detail. I just like to assure this august House that I have requested Dr. Abhijit Sen that we want his Committee's Report and I also said that if I don't get Report within 10 days, then those who are interested to understand this subject and those who know and those who have some definite views, I have no objection to call them, sit with them and take corrective action only on agriculture products, not other things.

श्री एस0एस0 अहलुवालिया: झारखंड): उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय ने आंकड़ों के जाल में और घोषणाओं की कतार में खड़ा कर दिया, मगर जो कल से सवाल उठ रहे हैं और साधारण लोगों के पेट पर इस महंगाई से जो चोट पहुंच रही हैं, उस आग को शांत नहीं किया हैं। ....(**व्यवधान**)... हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(कुछ माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए।)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, he has not replied to many of the issues ... *(Interruptions)...*

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, we are not satisfied with the Minister's reply. So, we are walking out..*(Interruptions)...*

(At this stage, some hon. Member left the Chamber)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 3.00 p.m.

The House then adjourned at five minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at fifteen minutes past three of the clock.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH) in the Chair]

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

Deteriorating position of supply of crude oil, LPG and other petroleum products in the country

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Shri Gireesh Kumar Sanghi. Not present.

Shri Vijay J. Darda to move the resolution regarding need to increase the indigenous production of crude oil, LPG and other petroleum products in the country.

SHRI VIJAY J. DARDA (Maharashtra): Sir, I move:—

"That this House expresses its deep concern over the deteriorating position of supply of crude oil, LPG and other petroleum products in the country in the wake of rising global prices of crude coupled with our dependence on around seventy five per cent of oil from imports and urges upon the Government to increase the indigenous production and gradually end the growing adulteration and diversion of highly subsidized petrol, diesel, LPG and kerosene to unintended beneficiaries by initiating following measures:—

(i) Optimum exploration and production of crude oil and gas from offshore deep sea bed or from on-shore wells;

(ii) Obtain fixed percentage of production of oil and gas at predetermined mutually agreed price from India-based consortiums working in oil fields or foreign-based consortiums where ONGC, Oil India or any other petroleum industry PSU is a partner;

(iii) Foreign technology, wherever found necessary, to be obtained or got transferred through agreements by ensuring that only "established technology" and not "obsolete" or "innovative technology" transfer is accepted;

(vi) Due to our depleting oil reserves either off-shore or on-shore, all out efforts are to be made to find alternative to oil through research and development inputs from our state-of-the-art laboratories in public or private sector;

(v) Gradual introduction of transparent cylinders for domestic consumers to enable them to easily view the quantity of the gas contained therein;

(vi) Break the nexus between the distributors and company officials by initiating severe punitive measures for diversion of domestic LPG to commercial/industrial consumers and unauthorized LPG-propelled vehicles through phase-wise launching of pilferage-free direct pipeline metered supply scheme; and

(vi) Streamlining the functioning of the oil outlets, LPG distribution network and kerosene-selling dealers with zero tolerance for any indulgence in corrupt-practices or diversion of subsidized petroleum products to unintended beneficiaries."

सर, सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण और गंभीर विषय हैं और इस सदन में माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि यहां पर पेट्रोलियमत्री उपस्थित होने चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री दिन्शा जे0 पटेल**): उनकी ताबियत ठीक नहीं हैं।

श्री विजय जे0 दर्डा: आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने उपस्थित प्रस्ताव के माध्यम से पैट्रोलियम उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों, गिरते उत्पादन सतत् मिलावट और एल0पी0जी0 की कमी से संबंधित पहलुओं पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। चूंकि यहां पर पेट्रोलियम मंत्री जी नहीं हैं, इसलिए मैं राज्य मंत्री जी के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैंने प्रस्ताव में सरकार से अपेक्षा की हैं कि कच्चे तेल और गैस के खनन में अधिक से अधिक वृद्वि हो, जहां कहीं ही हामारे ऑयल पी0एस0यू0ज0 सहभागी हैं, वहां से हमें निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कच्चा तेल और गैस मिले, नई तकनीक का सही तथा अधिकाधिक प्रयोग, शोध कार्यो में सरकार प्रयत्न करे, ऑल्टरनेट फ्यूल के बार में निश्चित नीति हो, गैस की सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर के बीच जो कडी बनी हुई हैं जिससे घेरलू प्रयोग वाली गैस व्यावसायिक प्रयोग के लिए ट्रांसफर हो रही है,वह रुके तथा कम्पनियों का आचरण पारदर्शी हो, वह तमाम आउटलेट्स ठीक से नियमानुसार काम करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं यह रिजोल्यूशन मूव कर रहा हूं।

तेल की राजनीति,तेल के लिए लड़ाइयां विश्व व्यापक हो चुकी हैं। मंत्री महोदय, "तेल देखिए, तेल की धार देखिए" हमारे यहां की राजनिति में भी यह विषय कहीं आप आदमी के संघर्ष का कारण न बन जाए। इसलिए इससे संबंधित विषयों पर विचार करना तथा उक्त समस्यों का समाधान बहुत जरूरी हैं। प्रस्तुत प्रस्ताव इसी समाधान की दिशा में एक कदम हैं। मैं आशा करता हूं कि सदन के अन्य सदस्यगण भी इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए, इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

हम तेल के खनन के क्षेत्र में नई से नई तकनीक के प्रयोग की बात करते हैं, नई तकनीक की खोज की बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मंत्री जी, खनन के क्षेत्र में इसका कितना प्रयोग हो रहा हैं? यह तय हैं कि मिलावट के क्षेत्र में पैट्रोलियम के क्षेत्र में ऐसी तकनीक का प्रयोग हो रहा हैं, लगता हैं जिसका समाधान सरकार के पास हैं भी यह नहीं भी ।

आज देश के कोने –कोने में ऐसा शायद ही कोई पैट्रोल पम्प हो, जहां आपको शुद्व तेल मिल पाए। ऐसी ही स्थिति में जब मेरी गाडी खराब हुई तो मेरे एक मित्र ने कहा-आप इसे मिलावट मत कहिए। देखिए, हमारा देश बहुभाषावादी तथा तमाम संस्कृतियों से मिलीजुली परम्परा का देश हैं। यह हमारी समन्वय की भावना हैं, जो हमारी संस्कृति को महान बनाती हैं। अब देखिए, गेहूं में मिट्टी , शक्कर और चावल में सफेद पत्थर, मक्खन और पनीर में सोख्ता और इलायची में कचरे का अद् भुत समन्वय हैं। तो भला पैट्रोलियम का क्षेत्र इस समन्वय की संस्कृति से कैसे अलग रह सकता हैं। मंत्री जी, क्षमा करिए, मैं शुद्व तेल की मांग कर के कहीं आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तेल क्षेत्र में यह समन्वय की संस्कृति कब तक चलेगी। कहीं पैट्रोलियम उत्पादनों में नैप्था, तो कहीं पेट्रोल और डीजल में केरोसीन। आज पैट्रोल पम्प के आबंटन के लिए होड़ लगी हुई हैं, क्योंकि आदमी मिलावट करके जल्द से जल्द धनवान होना चाहता हैं। उसे परवाह नहीं हैं कि उपभोक्ता इसके लिए कोई भी कीमत चुकाये। आज इन लोगों में मिलावट करके जल्द से जल्द से जल्द धनवान होना चाहता हैं। उसे परवाह नहीं हैं किउपभोक्ता इसके लिए कोई भी कीमत चुकाये। आज इन लोगों में मिलावट करने का डर नहीं हैं और जो कानून हैं, उनका प्रजातंत्र में उपयोग नहीं हो रहा हैं। मिलावट के कारण सिर्फ वाहन ही खराब नहीं होते, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा हैं। अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी एक रिपोर्त बहुत ही भयानक दृश्य उपस्थित करती हैं। उसमें कहा गया हैं कि प्रदूषण की वजह से तापमान में बढ़ोत्तरी होगी और जलवायु में परिवर्तन से देश के सभी तटीय प्रदेश प्रभावित होंगे तथा **कई** बड़े शहर जलमग्न हो जायेंगे। मुम्बई भी 20 साल में समुद्र की चपेट में आ जायेगी, द्वारिका बन जायेगी, ऐसा ये लोग कहते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मिलावट एक ऐसी समस्या हैं, जिसे आप राज्यों की जिम्मेदारी कहकर उससे किनारा नहीं कर सकते हैं। अधिकतर पेट्रोल पम्पों के मालिक ऊंचे रसूख वाले हैं या असमाजिक तत्व हैं, जिनके यहां पर जांच करने से अधिकारी कतराते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक साल में आपने कितने लोगों को पकड़ा हैं, कितने पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस निरस्त किये हैं और मिलावट को रोकने के लिए कौन से टेक्नीकल और इंस्टीट्युशनल कदम उठाये हैं?

इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न डोमैस्टिक एलपीजी का व्यवसायिक तथा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में होने वाले दुरुपयोग से भी हैं। रियायती दरों पर मिलने वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों का होटल, रेस्टोरेंट में प्रयोग हो रहा हैं तथा वाहनों में बिना रोक-टोक किए गैस सिलेंडर गैस डिपो से सप्लाई हो रहे हैं। गैस सिलेंडरों की कमी से दिल्ली भी अछूती नहीं हैं। साथ ही साथ गैस के सिलेंडरों में पानी मिलाया जा रहा हैं। बड़े गैस सिलेंडरों में से छोटे गैस सिलेंडरों में गैस भरकर इनकी खुलेआम बिक्री की जा रही हैं। मुझे यहां तक पता चला हैं कि एविएशन फ्यूल में भी मिलावट हो रही हैं। मंत्री जी, आप बताइयेगा कि यह बात कहां तक सही हैं?

बढ़ते मूल्यों की आंधी ने गरीब के घर की लालटेन और दिये को बुझा दिया हैं। यातनाओं के अंधेरे में गांव के गांव समाहित कर लिये हैं। दुष्यंत कुमार ने कहा था,

"कहा तो तय था चिरागां हर इक घर के लिए,
कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। "

जब भी तेल के मूल्यों में वृद्धि होती हैं, इसका सीधा असर गरीबों पर पड़ता हैं। किसानों को पहले से ही अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता हैं, तेल की कीमतों में वृद्धि से लागत में वृद्धि होती हैं। इसके साथ ही साथ हमारे समग्र औद्योगिक और आर्थिक विकास पर इसका असर पड़ता हैं। आईएमएफ के अनुसार तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि से हमारी आर्थिक प्रगाति की दर की डेढ़ प्रतिशत से दो प्रतिशत की गिरावट आयेगी। आईएम एफ के अनुसार यह कीमतें ऊंची रहेंगी, जो आगामी 20 वर्षो में हमारी अर्थ- व्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करेगी। आज हम देख रहे हैं कि पिछले दो दिनों के अंदर इनका मूल्य कल 112 डालर था और आज 115 डालर हो गया। पेट्रोलियम पदार्थों की ऊंची कीमतें हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोको खोजने के लिए विवश कर रही हैं। ब्राजील में 1975 से इथेनोल से कारें चल रही हैं। वहां पर 80 प्रतिशत कारों में फ्लेक्सी फ्यूल इंजन हैं, जिनका प्रयोग सन् 2003 से हुआ। यह इंजन पेट्रोल या अल्कोहल, किसी पर भी चल सकते हैं। इस तरह के प्रयोगों से ब्राजील की लगभग एक तिहाई जरुरत आल्टरनेट फ्यूल से पूरी हो रही हैं। मुझे लगता हैं कि हमारे देश में ऑयल कम्पनियां खुद नहीं चाहतीं कि एथनोल और बॉयो-डीज़ल का प्रयोग हो। इस संदर्भ में सरकार को अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिए। इस समय हम कितना एथनोल मिला रहे हैं, क्या हम 10 प्रतिशत का टार्गेट प्राप्त कर रहे हैं, आज हमारे यहां एथनोल का कितना उत्पादन हो रहा हैं, 10 प्रतिशत के मिश्रण के हिसाब से

हमें लगभग 130 करोड़ लीटर की आवश्यकता हैं, बॉयो डीजल की स्थिति क्या हैं और हमारे देश में जेटरोपा का उत्पादन कितना बढ़ा हैं? आज हमारे देश में जो वेस्ट लैंड हैं, अगर हम उसमें जेटरोपा उगाएं, तो किसानों के लिए यह एक अल्टरनेटिव उत्पादन का साधान हो सकता हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने भी इसके उत्पादन पर जोर दिया था कि जो हमारी वेस्ट लैंड हैं, उसमें जेटरोपा का उत्पादन करके किसानों के लिए नई आमदनी का स्त्रोत खोला जा सकता हैं। इस दिशा में भी आपके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं, यह मैं जानना चाहूंगा? एथनोल कृषि भूमि, सिंचाइ और आदानों की विद्यमान लागत के कारण इतना लोकिप्रिय नहीं हो पा रहा हैं, इसके लिए मंत्रालय ने क्या किया हैं, इस विषय पर एक स्टडी होनी चाहिए जिससे यह पता चले कि हमारे यहां अल्टरनेट फ्यूल की कितनी संभावना हैं या हम इसका कितना उत्पादन और मिश्रण कर सकते हैं। अभी मूल्यों में वृद्वि का असर यह हुआ कि रिलायंस और एस आर ने अपने पैट्रोल पम्प बंद करने का निर्णय ले लिया। सरकार की प्राइवेत सैक्टर के प्रति क्या नीति हैं? इन पैट्रोल पम्पों पर मंहगा पैट्रोल पम्प बंद करने का निर्णय ले लिया। सरकार की प्राइवेत सैक्टर के प्रति क्या नीति हैं? इन पैट्रोल पम्पों पर मंहगा पैट्रोल और डीजल मिल रहा था, लेकिन शुद्व मिल रहा था, इसलिए लोगों का उधर रूझान था। अभी टैक्स और तमाम तरह की ड्यूटीज़ मिलाकर एक लीटर पैट्रोल पर 25 रुपए के लगभग खर्चा आता हैं अगर इसको कम कर दिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय दामों में वृद्धि का उप्भोक्ताओं पर कुछ न कुछ असर कम होगा, ऐसा हमें लगता है।

भारत की जो 70 प्रतिशत जनता गावों में रहती हैं, बढ़े हुए डीजल के दामों का असर उसकी उत्पादक क्षमता से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता हैं। इससे किसान भाई भी बडी मात्रा में प्रभावित होते हैं। नई तकनीक और हमारी उत्पादन क्षमता के लिए, इस विषय पर आगे बात करने से पहले हम O NGC के बारे में CAG की रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। CAG ने कहा हैं कि ONGC की गलत planning की वजह से ठीक समय पर निर्णय न लेने से, दूरदृष्टिता के अभाव और सम्यक् निगरानी के अभाव से इस विभाग को निश्चित रूप से 2482 करोड़ रुपए की बजाए 3286 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, करीब-करीब 800-900 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़े। हमारी तेल कम्पनियों में व्यवसायिक क्षमता होनी चाहिए, वे भी सामान्य ब्यूरोक्रेसी की तरह काम कर रही हैं। अगर हम नई नकनीक की बात करें, तो हम यह तकनीक हम जिस हाथों में दे रहे हैं और जो टैक्स-पेयर का 900 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। यह निष्कर्ष तो कुछ तेल के कुलों के ऑप्रेशन के बारे में हैं। बाकी तेल कम्पनियों का रोल भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा हैं। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 10th five year plan के आपके क्या टार्गेट थे और कितने एविच हुए और 11^{th} five year plan में आपके क्या टार्गेट हैं? तेल-शोधक कारखानों में ईंधन क्षति को कम करने की सख्त जरूरत हैं। ऊर्जा खपत को कम करने के लिए 7200 मिलियन रुपए की राशि वाली परियोजनाओं की पहचान की गई थी, जिसके कार्यान्वयन से 186000 टन ईंधन क्षति की बचत होती। सरकार सदन को बताए कि पचास करोड़ की लागत या उससे ऊपर की कितनी योजनाएं सरकार के पास लंबित हैं तथा कितनी योजनाएं दो वर्ष से अधिक की हैं तथा इन पर कितना खर्च बढ़ा हैं? आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने तमाम लंबित परियोजनाओं पर क्षोभ व्यक्त किया था, इसके क्या कारण हैं? तेल कंपनियों द्वारा प्रयुक्त तकनीक और प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी हैं। इस संबंध में आपकी तेल कंपनियों ने रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर कितना खर्च किया हैं तथा नई तकनीक के आदान-प्रदान की क्या स्थिति हैं? नई तकनीक के अभाव में नए तेल भंडारों के समय पर और कुशलतापूर्वक खोज करने के मामले में ढिलाई हो रही हैं। ओ0एन0जी0 सी0 अपने असम तेल क्षेत्र में तेल निकासी के सुधार के लिए 37 बिलियन रुपए का निवेश कर रही हैं। आपने तेल और गैस क्षेत्र में सुधार और तकनीकी विकास के लिए व्यापक आधुनिकीकरण योजनाएं क्यों नहीं तैयार की हैं? क्या इस आरोप में सत्यता हैं कि ओ0एन0जी0सी0 सिर्फ अपना ध्यान असम पर केन्द्रित कर रही हैं तथा गोदावरी और मुंबई हाई-वे जैसे क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही हैं। विश्व भर की तेल कंपनियां जिनमें चीन भी शामिल हैं, तेल ब्लाकों का अर्जन कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ओ0वी0एल0 की इस मामले में क्या स्थिति हैं? आपने चीन और अन्य देशों के मुकाबले कितने ब्लॉक हासिल किए हैं। आज तेल कंपनियों की लागत विश्व में सर्वाधिक हैं। क्या आपने विश्व की अन्य तेल कंपनियों के साथ कोई तुलनात्मक अध्ययन किया हैं। जिससे पता चले कि आप जो एस्टेब्लिशमेंट, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य मदों पर खर्च कर रहे हैं उनकी अन्य देशों की कंपनियों के साथ साथ क्या स्थिति हैं? हमें पता चला हैं कि काफी पैसा तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा विदेश घूमने पर खर्च किया गया हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अगर नई तकनीक, प्रशिक्षण इत्यादि पर खर्च हुआ हैं तो ठीक हैं, परंतु इसका परिणाम क्या रहा हैं? इसमें से हमें कितना फायदा मिला हैं? अभी तेल कंपनियों का उत्पादन लगभग स्थिर हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में घरेलू उत्पादन में 41 प्रतिशत वृद्वि का अनुमान हैं, लेकिन खपत और आवश्यकता कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में क्या अनुमान हैं? एक अनुमान के मुताबिक अगले पांच सालों में खपत में 53 प्रतिशत वृद्वि के आसार हैं। ओ0एन0जी0सी0 को भी रिगों की कमी का सामना करना

पड़ रहा हैं। कई ऐसे ब्लॉक्स हैं, जिन्हें अवार्ड दिया गया हैं, लेकिन उत्पादन शून्य हुआ हैं। ओ0एन0जी0सी0 के पुराने कुओं पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई थी, इस 14,000 करोड़ रुपए की योजना पर रकम किस तरह खर्च की गई, तथा पुराने कुओं, जहां यह रकम खर्च की गई, वहां कितना उत्पादन बढ़ा? पिछले एक साल में वास्तविक अन्वेषण में कितना खर्च हुआ तथा कितने अन्वेषण हुए? ऐसे कितने पुराने रिग्स हैं जिनकी मरम्मत का कार्य हुआ था कितने ऐसे रिग्स हैं जो मरम्मत के लिए लंबित पड़े हुए हैं? झारखंड में कोल बेड मीथेन की काफी संभावना हैं, इस पर कितना काम हुआ हैं? हमारे यहां कितनी उत्पादक क्षमता हैं तथा कितना उत्पादन हो रहा हैं? ओ0एन0जी0सी0 बारह विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर महानदी और कृष्णा-गोदावरी बेसिन में उत्खन्न की संभावना पर काम कर रही हैं। उनके साथ करार करने की क्या स्थिति हैं और कितना काम हुआ हैं? यह कहां तक यशस्वी हुआ हैं तथा इस करार की स्थिति क्या हैं? मार्च , 2008 में हमने सागर निधि नामक पोत का लोकार्पण किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में हैं, क्या आपको डीप सी बेड से ऑयल एक्सप्लोरेश या गैस के बारे में रिसर्च या डेवलमपेंट के बारे में इस मंत्रालय से कोई सहायता मिल रही हैं?या आपने इसके बारे में क्या कोशिश की हैं? ईरान –पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन मुझे एक मृग मरीचिका लग रही हैं। समझौते की क्या स्थिति हैं, कोई नहीं जानता। काम कब तक शुरू होगा, हो सके तो मंत्री जी बताने की कृपा करें। इसी तरह तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौते की क्या स्थिति हैं?

गेल, इंडियन ऑयल, एचपीसी, भारत पेट्रोलियम जैसी आपकी सारी इकाइयां हैं। इनके कार्य की जो जानकारी मिलती हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी का अभाव नजर आता हैं। इस दृष्टि से आप बताएं कि उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

ईंधन की खपत और इसके सम्यक उपयोग के लिए हमें ढांचागत सुधार की जरुरत हैं। क्या सरकार ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े वाहनों तथा जाम वाली स्थितियों में होने ईधंन की खपत का अनुमान लगाया हैं? एक अनुमान के मुताबिक अगर हम सिग्नल प्रणाली को ठीक कर लें, तो सालना 1,200 करोड़ रुपए की बचत हो सकती हैं। इसी तरह विमानपत्तनों पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण विमान आकाश में घटों चक्कर काटते हैं। इस ईंधन की बर्बादी को बचाया जा सकता हैं। इसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... इसके लिए आपको प्रफुल्ल पटेल जी के साथ समन्वय करना पड़ेगा। साथ ही, जो हमारे खराब रास्ते हैं हमारे देश में, उन्हें अच्छे बनाने होंगे। जहां-जहां ईंधन का बचाव किया जा सकता हैं, सरकार को करना होगा। इतनी मंहगाई हैं, क्या इसके लिए आप कोई योजना बना रहे हैं, हम यह भी जानना चाहेंगे?

ओ0एन0जी0सी0 तथा अन्य तेल कम्पानियों में तैनात वैज्ञानिक और इंजीनियरों का भारी मात्रा में पलायन जारी हैं। ये इंजीनियर बेहतर वर्किंग कंडीशन के लिए प्राइवेट या बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को ज्वायन कर रहे इस स्थिति से निपटने के लिए आपने क्या किया हैं तथा पिछले तीन सालों में पलायन की क्या स्थिति रही हैं और उसको रोकने के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं? आज इन सब बातों को देखते हुए और चूंकि यह निजी जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग हैं, जिससे हमारी जो आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उनके लिए यह बहुत आवश्यक हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैनें यह प्रस्ताव यहां पर लाया हैं। धन्यवाद।

The question was proposed

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate Shri Vijay Darda for bringing some important points, by way of a Resolution, before this House. As he has rightly said, this issue has attracted the attention of all and it needs to be looked into urgently by the Government as also the concerned companies. India has got indigenous production potential in oil and gas and our country is benefited by the help of Russian technology in finding out the areas of availability, whether it is onshore or offshore. The data was collected, we started working on it and we are benefited by that. During the NDA regime, they started to mark areas with heavy potential as areas with less potential, and they sold these wells to the private sector. The private sector started to purchase those potential areas at cheaper rates. When the shareholders' meeting was held, those private

sector corporate bodies and their CMDs started saying, "We are happy to announce that the shareholders are going to earn a huge money as these wells are giving a very huge output".

That was the administration, during the NDA regime, because of which v/e suffered. Huge money was transferred; huge assets were transferred to the private sector without proper compensation to the country. Our own production also suffered during that period. When the price of oil was only 35 dollars per barrel, people were taxed at that time also. People had suffered a lot. When this Government came to power, hon. Shri Mani Shankar Aiyar, after taking over this portfolio, found that our nation was having a great potentiality and that we could go there and take those areas for our people. He made the public sector companies to bid in other countries also. We have succeeded in many areas. Our own production has increased. We are having a confidence that even if there is scarcity, we can meet the situation. That was the period when even the Americans, the Secretary of State, came here and said, "Why are you having a plan to transport gas from Iran to India through Afghanistan? There is a security risk. Therefore, don't do it." This kind of pressure was there on us. Subsequently, we went ahead with that task. Even though we have not succeeded in that area, but we have got the potentiality. Already, we have located places which can be beneficial for our nation. Therefore, I request the Government to take up those ventures. We need not worry about those countries, who want to dominate other countries, who want to throw a war on other countries on some false pretext, simply to grab oil resources. We need not do that. Wherever possible, India should try to get those resources commercially. When we compete with our technology at the international level, we increase our wealth and our country is benefited by that. When the private sector goes in for those resources, it is they who get strengthened, not the nation because the profit which they earn, they invest that profit in other countries, not in India. We can see that our nationalised banks are giving huge money to the private sector and the private sector is investing in other countries. They are earning profit in terms of dollars, not in terms of rupees. So, in no way are we benefited. Our exchequer is not at all benefited. Oniy a handful of people are benefited. We have many multinationals in India. No doubt, we are also proud of them. If they succeed in commercial ventures, we congratulate them. But, at least, let them divert some profit to India. If they get the technology, if they get resources, let them bring that to India first; let them give that to the motherland first and then they can go in for marketing at the international level. At the same time, I wonder why we are not allowing companies from other countries to compete in India. Many companies of the world are ready to come and invest their money in India because it is a huge market. We have already opened up our market for automobile production. Many South Korean, Japanese, American and European companies are putting up their production units in India, in places like Chennai. They feel that a certain portion of their production can also be sold in the Indian market. Now, we are allowing cars to go to our. villages. We are happy about that. We have various projects under which we are making good roads in our villages. People are becoming very rich overnight by selling their agricultural 1 lands, the lands on which they were producing food for their family, their village community and others. It is just like a story that used to be told earlier; that there was a person who had a goose which laid golden eggs. He was very ambitious and greedy. He thought he would kill the goose and in just one day he would get all the eggs and become rich. But, finally, when he had killed the goose, he found only small eggs and he could not succeed. The same thing is happening in agriculture. In Tamil Nadu, the entire coastal belt has been sold to multi-national companies. An acre of land which was earlier available for Rs. 10,000 is now being sold for Rs. 2 crores. How will that poor agriculturist consume this amount of Rs. 2 crores? He cannot even count that money. So he has started building big houses as a result of which

steel prices are going up and the prices of cement and other building material are going up. But he is not worried about it. He is buying consumer goods from the market. The inflation is going up. Now, we do not have any data. The Finance Ministry cannot find out for how much money that land was sold by A to B, B to C, and so on, how much money the intermediary got in the deal. The income tax officials are also not worried about it. They can't find out the extent of the black market economy that is operating now in India. Therefore, inflation is going up on the one hand. On the other, new assets are being created by people. They cannot manage their assets. They do not have any knowledge about managing those assets which were created overnight. This is what is happening. The demand for petrol is going up. The demand for diesel is going up. Thousands of cars are running on our roads. There is no planning as to how to control this traffic whether at the State level or the national level. We find traffic jams everywhere. We are allowing the black market economy to work. We do not have any data. We are just taxing the salaried people again and again and we claim to have collected huge money in that way. We are taxing people in an indirect way, through all other sources. But we get that money only in a small way. We are not able to control that also. The corporate sector is giving some money to the exchequer and with all this money we are running all our national programmes. In one way, we are losing our land for which we had fought during our freedom struggle, during the East India Company period; our forefathers had tilled that land and toiled with their blood and sweat. That land is now in the hands of multi-national companies. We do not know the name of the companies but the land is in somebody's hands. What are they going to do with it? Are they going to put up their industries there? No. They are going to borrow the money from our own banks and keep it as a wasteland and, then, convert for agricultural purposes or horticulture and, in the next season, they are going to say, because of drought, nothing could be produced. Then, we will write off that debt also. That multinational company will enjoy all the benefits given by our nationalised banks. This is a vicious circle which is coming up. Sir, no exact data is collected how the black-money is coming up. Our hon. Finance Minister could not come up with those data when he presented the Budget. He could not give us the data how much money is in the hands of those people, how we are going to monitor it, how the inflation is going up and what is the reason for it. We may be telling that since the foreign countries are increasing the prices, therefore, we are also suffering. No, it is not like that. We are having the surplus money in the hands of a few people. This surplus money is even in the hands of ordinary people who do not know how to spend that money. But, they are putting all their liquidity or money in the market. Therefore, the prices are going up. If the vegetable prices are going up, we can find whether the vegetable is grown. If it is not grown, then, the price goes up. The demand is high. The supply is very low. Therefore, the price is going up. We can say like that. At the same time, the other thing is happening. There is availability of vegetables. The people are ready to purchase it by giving more money. That man did not eafn that money. He surprisingly got it by selling his own land, by selling his own egg-laying goose. That is the reason why the price is going up in villages. But, the salaried people are the ordinary people are saying that the Government of India is not controlling the price, therefore, it is going up.

Sir, there is another situation which is coming up. There is a heavy demand of petrol, diesel and all other fuels. How are we going to manage that situation? Are we going to have the Regulatory Authority? We have passed the law, but the Act is not at all notified, I hope. The Regulatory Authority is not constituted. The Regulatory Authority is not given the power and we are not allowing the foreign countries to come and compete with us in selling their own diesel, petrol and other products which are needed for our people. We are controlling

ourselves by allowing a certain number of private sector companies to enjoy all the benefits and earn profit. We are allowing the public sector to suffer then and there. If we do not allow them to come out of their debt net, then, finally, one day, we will find that our own public sector is totally gone from our hands. Just like the BJP had sold it in the last five years during its regime. They sold all the National Textile Mills. Out of 110 mills, they left only 20 mills. In the rest of the mills, they even sold the land, the real estate. They sold it by saying that the NTC could not earn profit. When the textile industry was in the high, when the private sector was earning huge profit, they were selling our own land, our own machinery to the private sector. That was the end which was going to come. The people have to be educated that this is the situation which is emerging. Therefore, we have to see to it how we are going to address the situation regarding fuel. The petroleum products like diesel and petrol should become the common man's day-to-day affair. A person who does not go out of his house is not at all accepted by the public. He has to go out somewhere. At least, he has to go to the cinema. If he cannot go to the cinema, at least, he has to go out for socialising with his family and others. They have to go out for a small tour. Therefore, they depend on the transport. Now, the public transport is totally occupied and the people have started to own their own vehicles like two-wheelers and four-wheelers. How are we going to give them fuel for these vehicles? How are we going to charge for diesel and petrol which is being used by the common man? If we increase the price of petrol and diesel to that of the international market, then, automatically, the people will agitate. There will be strikes; there will be processions; there will be shouting. At the same time, we have to see whether we are going to make the public sector to suffer again and again. Are we going to transfer this burden to the consumer? No doubt, Sir, the prices of kerosene and LPG can be controlled; it can be regulated because we want to protect our forests. Already the forests have been annihilated by the people. After bringing the usage of LPG in villages, we find that wood-cutting is coming down. We do not have any exact data on that aspect. We can practically see that even ordinary persons are using LPG in their homes instead of collecting wood and cutting green trees. In the same way, we can control the use of kerosene also. In one way, we can get a feedback from the tribal areas. The quantum of kerosene given to the tribal areas is reduced and we feel very unhappy about it because there is no electricity in the tribal areas. There would be cottages here and there and they have to depend on kerosene only. Likewise, in the far-flung areas, there would be a distance of one kilometre from one house to another. In those places, electricity is a luxury. The authorities are also not ready to give them the supply of electricity. Therefore, those people too have to depend on kerosene.

Sir, there is also another side of the story in urban areas in the name of kerosene. A few people are enjoying the reduced price on kerosene. The exchequer is burdened with the subsidy given to them. In the semi-urban areas also, certain quantity of kerosene is given. But what a few people are doing? They are getting the family cards very easily. The State Governments too are not at all worried to inquire about the number of family cards that are used by the genuine card holders, actually. Family card has now become a 'gold bond'. It is very easy to transfer into somebody else's name. That can also earn a monthly salary to a few people. That can earn a quick money of Rs. 10,000 or Rs. 15,000. It can earn that much. I can even mention, Sir, that certain political parties are maintaining certain people for holding a thousand cards in their hands, two thousand cards in their hands. In city areas, they can hold even five thousand cards! How are they getting these? The Governments may change, but these people will not chang! There is a saying: Indra may change but the Indrani will not. In the same way, the Governments may change, but the people who are holding family cards

4.00 P.M.

will not change. In fact, they will increase holding the number of cards saying that the poor people are not given the cards, and they go on getting bogus cards! No effort is taken by Government of India and also by the civil liberties group or by persons who are interested to see to it that this type of unnecessary expenditure for the exchequer is curtailed. Therefore, they are going on increasing the wealth. They are getting huge money by selling kerosene. They are getting huge money by transporting rice from Tamil Nadu to Kerala, from Karnataka to Kerala and for other places also. The same thing is in North India also. Very easily they can transport wheat. This is the situation. When we are giving new schemes for the people, we should have a social audit.

We find that the Rural Development Ministry is doing a wonderful job in implementing the National Rural Employment Guarantee Scheme by way of social audit. They put it on the website itself as to how much wage a particular family is getting on a particular day. To that an extent they are transparent. The same way should be applied for the Department of Civil Supplies also. Biotechnology method should be followed, bio-metric way of issuing the cards should be there so that the individual who has got that identity alone is allowed to purchase in a particular shop. That should not be allowed if the card is transferred to anybody. We should restrict its use by that family alone. In that way, we can reduce the retail outlets which are having the luxury of selling kerosene in the open market.

Sir, with regard to diesel and petrol, I find that in many cases, ordinary middle-class people are suffering. The middle-class people who have a salary of a certain limit, like Class-D or C, should also be given some identity cards by which they are helped. For using that card some discount can be given. By blatantly reducing the burden of the international price rise, and by way of universal method of subsidising, you are helping the rich people rather than the ordinary people. Therefore, ordinary people should be segregated and middleclass may be segregated. It may be an onerous task but we can do it by using technology. We can do that through a method of leaning, we can do that through a professional method. We can find out how much we are consuming and whether the consumption is within the limit. The people who are having a very limited income and limited expenditure also, they have to be helped by giving subsidy. But rest of the rich people who are having five cars or ten cars, why should we subsidise those cars for petrol and diesel? Why should we allow them to enjoy the taxpayers' money? They should pay for the money which is there is their hand and which is surplus for them. When they have five cars or ten cars, why should they not pay for it? Let them pay for it. But a person who is having a two-wheeler or small second-hand motorcar to carry the entire family, he should be subsidised. Therefore, the policy of subsidy should also be totally reviewed. We have to assess the income of such people and find out how best they can be helped by way of subsidy. If we have this method of common identity card, by this we can find out their profession, their income, their voter list names, their entitlement from the ration shop and every other thing can be put in this single card just like the credit card. By having a technical method, we can use it, and the data can be quickly assessed at the national level and also we can give subsidy to those people who cannot meet their needs through their income. The next thing I would like to submit is that LPG is a very, very important thing, which has to be taken into consideration. The womenfolk are very much dependent on it. The LPG should be a frozen type of thing for these types of families. They should, according to their income, have certain type of freezing. If there is a fluctuation, It should not affect those families because if a family earns about Rs. 2000 per month, it cannot bear a quick hike of Rs. 200 in its price. But at the same time,

a person who is earning crores of rupees, he can very easily pay for it. Therefore, there should be a classification of rich people who are able to afford and who are paying income tax at certain level and they should be asked to pay the price, which is prevailing in the international market. People who are having low income or the medium income, their families should be exempted from it, and they should be given subsidy. The universalisation of subsidy is not helping those people who are actually suffering because of it. But, at the same time, it is making the rich people richer. Therefore, that aspect has to be taken care of. While concluding, I would again like to come to the production and we have to start with technological methods to find out how best we can go in for hydrocarbon and now itself we have to start our unconventional methods of getting power. We have got lot of wind energy throughout the coastal areas. We have got solar energy. Throughout India we are having the solar energy. The apparatus, which is used for the purpose of households, is very.very heavily taxed. It also needs huge investment. Therefore, if there is mass production of solar energy producing material, then the price will be very, very low and people will purchase it in bulk. An electric bulb can be purchased by paying ten or fifteen rupees but for the same solar bulb they are charging from Rs. 200 to Rs. 300. For a battery cell they have to pay Rs. 500 or Rs. 1000. Therefore, it should be reduced. There should be mass production of batteries by using solar energy so that we can enjoy. That energy will help us. We saw this when we had gone as a Committee to Rajasthan. Our own public sector undertaking has made a research by way of a battery system for drawing water from the well for agriculture through solar system. That type of system has to be given to the agriculturists and that is a very renewable source of energy. That is easily available without paying any charges. Therefore, that type of solar energy utilisation by the agriculturists for drawing water from wells, tubewells can be done. Also streetlights, public places, houses and small scale industries should be given solar power. Very big companies should also be compelled to use only solar power and should not go for electric power. When we are going for production of electric energy by utilising oil, then, we need huge budget. That can be reduced by this method. Regarding private sector participation I feel, Sir, that we should open up the market if you want IT sector to come up. Also, telecommunication is very, very cheap. When I came to Delhi as a lawyer to practise in the Supreme Court, I invested money for purchasing a small mobile phone. The lowest price of a mobile at that time was Rs. 12,000. The highest price was Rs. 50,000 or so. To speak for a minute, I paid about Rs. 12, Now; it is very cheap because we allowed competition to come here. Even for Rs. 1000 or even for Rs. 500, a mobile can be purchased. Certain companies are giving free mobiles if we get a SIM card and they are giving free accessories nowadays. Therefore, this type of universalisation should be made for this sector also. For that, we have to allow international competition to come to India. The Government should feel that the people who are regulated by way of income, their purchases should be subsidised and not for other people who can earn money through the market system. With these words, I appreciate the effort of Shri Vijay Darda who allowed us to have a loud thinking on this subject. Thank you.

SHRI RAHUL BAJAJ (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir; I will take much less time than my two other friends who spoke before me so that after me, Mr. Arjun Kumar Sengupta can speak. I do not agree with some of the points which the previous speaker said but I agree with some of the points which he said. Let me first mention the things with which I agree. I stand here to support and show my appreciation for the Resolution proposed by my brother, Shri Vijay Darda. Though he belongs to a different party and 1 am an Independent, the point where I agree with the previous speaker is: why are we subsidising for the rich?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): You belong to the UPA.

SHRI RAHUL BAJAJ: I belong to India and to the Indians. I also belong to Mr. Raja. Brindaji is not here; Yechuryji is not here. I also belong to them. I will refer to you, Mr. Raja. I cannot make a speech without referring to you at least once. But more seriously, Sir, why are we subsidising petrol and even diesel? Diesel is for trucks and buses. I will come to that later. I can understand the poor who are living below the poverty line. That statement you made and I agree with that, but I do not agree with the other statement you made that tax payers' money cannot be used, I say, even to subsidise car owners or even two wheeler owners. I am saying something, which is against the two-wheeler manufacturers, but the reason I am saying is that because I know nobody will listen to me in this Government. They will not follow my advice. They will not follow my advice. So, I can say with quite a bit of comfort. I refer to three issues on this broad subject.

First is energy security. Without affecting food security, we have to secure energy security. I was very happy to hear Shri Sharad Pawar saying today that India is not using corn for production of ethanol. We are not like America growing maize and transferring corn for ethanol production and subsidising it. But, they have their own reasons. We cannot afford it. I say that energy security is important for everything, but not at the cost of food security. He said, 'Molasses, trash, rubbish is used for producing ethanol.' I do own a sugar mill in UP. I have 14 units which my nephew runs. He does not listen to me all the time. But, that is another issue. I want to support industry. I am a private sector man. But, food security is first. That is how it is to be. We are not affecting the food security. If we affect food security, then, I am not in support of it. How do I now get energy security? It is nothing but produce more and more and if at all, without hurting the poor, consume less. But, that is only the way you bring a balance. Until there is no balance, there is a premium, there is a black-market, there is malpractice, there is adulteration and there is everything. I know that the Government will not listen to it. But, charge the right price. I shall come to poor. I want to hel the poor. I am not less than anybody else here in helping the poor. I may not be as poor as Mr. Raja. But, I am not a rich person than Mr. Raja. So, Sir, subsidising not only of petrol and diesel, I will come to LPG and Kerosene later, is wrong. The world is short of crude oil. It was mentioned - everybody born here by 1970 - that the price of crude oil in 70s was US $ 1 V2 per barrel. In three years time, it became US $ 3 per barrel. We started shouting. It went up to US $ 25, 35, 60, 100, 112 and two days ago Mr. Chidambaram said that today it is US $ 115 per barrel. Earlier, the oil producing countries were being exploited by the West and the developed countries. Today, in my view, the oil producing countries are exploiting the world, especially the developing countries. We suffer both ways. Anything which is in short supply, you are artificially creating a demand by keeping the price low. How can we care about poor? I will come back to that. If it means, Rs. 100 per litre for petrol, charge Rs. 100 per litre, not Rs. 40. Why are you artificially creating demand? You are saying public opinion, public opinion, public opinion. Fair enough. Of course, kerosene, should go cheap. But, no. It does not go cheap. We heard Mr. Sharad Pawar saying that there is 100 per cent diversion of foodgrains meant for BPL. Where is it going? It is being exported. That is how the trader is making money. That is how unscrupulous politicians, bureaucrats and businessmen are making money. But, we are giving them a chance, a chance for making money by creating a situation. You create all problems in the name of poor and then you say adulteration. Of course, Kerosene will be adulterated with everything else. Then, you say malpractice चोर हैं, बदमाश हैं, अरे । ह् मून नेचर हैं। यहां कौन गांधी हैं? यहां कौन विनोबा हैं? 95 per cent of us will cheat if we get a chance by

इलैक्शन का पैसा लेना, किसका पैसा लेना , All excuses.Sorry. So, let us not create a situation when we are tempted to cheat. Petrol prices are artificaly subsidized, diesel much more artificially subsidized! Charge the cost of production. Of course, it depends from refinery-to-refinery.But roughly, the cost of petrol and diesel is about the same. अब यह कार वाला हैं,? वह ट्रक वाला है। लोग भूल गए। लोग भूल गए कि आजकल मर्सिडीज कार चलती हैं, 70-80 लाख की, एक करोर रुपए की, उसमें डीज़ल जलता हैं माणि शंकर जी। There are few numbers. It is fair enough. I say, you charge the right price अभी बी बांड दे रहे हैं। fiscal deficit But forget that for the time being. आर्टिफिशियल डिफरेंस हटाओं, उससे एडल्ट्रेशन कम होगा। जब तक क्रूछ ऑयल रहेगा, पॉल्यूशन रहेगा लेकिन एडल्ट्रेशन से पॉल्यूशन और बढ़ता हैं- वह कम होगा। yes, my friend, Vijay Darda, said about better roads and this and that. At that will help. Mr. point is, produce more. I disagree with the previous speaker. He said something about private sector and public sector. He said that public sector will suffer and private sector will not suffer. I said before also that monopoly is terrible. In monopoly, I prefer the monopoly of the public sector to that of the private sector, both are evils, both hurt the customer. But, I had rather have a public sector monopoly than a private sector monopoly. But what we need is competition. I agree with that. That is the only Guru I keep repeating that forces us to be efficient and honest. I was making Bajaj Chetak scooters with ten-year delivery period क्या प्रीमियम था । डीलर या ब्रोकर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, जिसने बुक किया था? आज हमारा पल्सर या प्लैटिना बिकता नहीं हैं। हीरो होंडा भी हैं, टीविएस भी हैं, किधर चोरी करेगा, किधर ब्लैक हैं। It is not that Rahul Bajaj or Brij Mohan Lai is efficient or honest. Competition is forcing us. पब्लिक सेक्टर में जितना बनाना हैं, बनाओ। किसने मना किया हैं?

You are subsidising them. You are not subsidising my another younger brother Mukesh Ambani. But, I don't stand here for him. He did not bring me to this*. I am sorry. I seek an apology. I came here on my own because of some friends of mine. But, I admire his success whatever may be the basis. You said that some of the petrol stations are closing down. It is because he cannot sell at that price. What he does is his creation. I am not here for him. I am here for the Indian people. You talk of the private sector, public sector, OVL, public-private partnership etc. and whether Laxmi Mittal comes with somebody or not. All should be encouraged. If you stick to private sector public sector will close down. Why will it close down? It is because they will become inefficient. Why should they become inefficient? We have the Chairman of the Indian Airlines and there are some outstandingly competitive people. But the problem is of interference. There is political and bureaucratic interference. I will say that repeatedly. Why don't we give them autonomy; genuine autonomy? We are not prepared to give that. Everywhere, Sir, we are causing the problem. Let the private sector come in. I say that you expand the public sector if you can. It should be based on merit. No preference should be given. This is India, Sir. There is, what I call, and even others have called, the national sector. There is no public sector or private sector. I am not against multinationals. Let us fight. Let us not fight among ourselves. क्या बात हो रही हैं? खुद ही एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, पब्लिक-प्राइवेट वगैरह। It is not correct. We should compete with other countries of the world. In this connection, I would just like to make one more point. I said that I will speak less than the previous speaker.

In its own way, I admire China expect for its dictatorship and absence of democracy. I do not like that, Sir. They have achieved military success. I am not a supporter of that. They are much ahead of us. I cannot forget 1962.1 should forget 1962 also. I cannot do it. They have achieved economic success etc. etc. Let us not go into the reasons of that. They started liberalisation in 1979. We started it only in 1991. Mainly, it is the question of the system of

* Not recorded.

Government. Here nothing works. The Indian entrepreneur, farmer, service sector, IT, industrialists, trader, majority of them are good. A few of them are bad. They are in every sector. They are in every field, including politics. But a majority of them are good, that is why, India's growing at 8.5 per cent to 9 per cent for the last four or five years. It is not because of the Government. I would not say in spite of the Government, but, definitely, not because of the Government. They have said that they have done this and that. Yes, they have done this and that. They have filled half the glass. The bottom half is what I talk about and I want that full for that poor *admi.* China is *too* dangerous, Sir. We cannot afford to fight against too strong a nation. Frankly, I am not happy with what is happening *vis-a-vis* Tibet. I feel, we are afraid of China. People are saying to me, "No; no, Rahul, you don't understand diplomacy. Everybody sees his interest." Of course, I must see my interest. China keeps saying Arunachal Pradesh is theirs. China on its map, still does not show Sikkim as one territory, which they had agreed to. They questioned my Prime Minister going to Arunachal Pradesh. He said, "वीजा ले लेता अगर दूसरा आदमी जाता तो। I am saying, 'Tibet is yours, Tibet is yours.' I am a man like Dalai Lama was publicly told. "You are my honoured guest; I like that, but don't do anything to hurt my relationship with China. Say this to him privately if at all you want to say that, whoever it is. Don't say it publicly. I feel you are saying it to please the Left and also to please China. Sir India has a population of over 100 crores. We don't have to be afraid of China. We work with them but let us not be afraid, neither of China nor of America. China is conquering the world. Nobody knows this better than Shri Mani Shankar Aiyar. He has travelled the world over for that. He may have his own views on Iran-Pakistan-Afghanistan-India pipeline etc. but Latin America is being conquered of raw materials, not politically, by China. Let is talk about Sub-Sahara Africa. We are doing a little bit. The present Minister of Petroleum went to Carcas in Venezuela. He spent two bourse with Mr.Chavez and said," I have got something from them; fine, Sir. China is conquering the raw materials including the energy resources, mines, coal all over the world. I believe we are moving at a speed which is not even five per cent of that. I think Shri Mani Shanker Aiyar was doing a good job. Shri Murli Deora is my close friend; he is like a younger brother; Mr. Aiyar was doing a good job. I don't know why he has been shifted. I disagree with him on sports because I am a good friend of Shri Suresh Kalmadi. But, that apart, let us cooperate with China wherever possible, but we cannot depend on China. We have to conquer the raw material resources of the world by ourselves.

Sir, my last point is about *aam aadmi.* You said something about the Identity Cards. I just want to tell you.How to determine the logistics can be worked out. But I want market price, no subsidy; I do not want cross subsidisation or subsidising kerosene fully. LPG is almost fully subsidised. Then comes diesel and lastly, petrol. I don't want that.I will say that goes against my interest. I am a two-wheeler manufacturer, but I am an Indian first. My family, I can't take credit for them. They were great, I am not. I can't take credit for them. I am very ; lucky that I have got that legacy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Please conclude.

SHRI RAHUL BAJAJ: जैसे एजुकेशन के लिए, हैंल्थ के लिए हर कोई जाता नहीं हैं। We make cards like Identity Card, PAN Card, etc. Then, below the povertyline, hopefully without corruption "राहुल बजाज, मेरा बच्चा जाता हैं प्राइवेट स्कूल, There are better schools also, but in majority of the Government schools, we all know, there is no teaching. My auto-rickshaw driver in Pune told me, मुझको उसको डाक्टर, इंजीनियर बनाना हैं,, half of my salary goes in for paying fees f my three children ऑटो रिक्शा ड्राइवर नहीं बनाना हैं। said, "you are right."

उसको छोडिए अभी केरोसीन का लीजिए,why should diesel or petrol be subsidised? I don't agree कुछ तो हिम्मत रखो as a Politician, Become a Statesman. Explain to the people. खूब नारे लगाएंगे, वह तो रास्ते में आ जाएंगे अगर प्राइस बढ़ गई तो। आने दो क्या होता हैं, पॉवर में कौन हैं। पब्लिक ने वोत दिया हैं आपको, देखेंगे क्या होता हैं। अगले इलेक्शन में क्या होता हैं, डरते क्यों हो। तो वाउचर दीजिए, for below the poverty line. उससे वह केरोसीन खरीदेगा, उसको सौ, दो सौ, पांच सौ का दीजिए यह वह बेचेगा। I do not mind. उससे डेस्टॉर्शन नहीं होता, पैल्यूशन नहीं होता, एडल्ट्रेशन नहीं होता। Except वह बेच सकता हैं। वह जो डिटेल्स की बात , So, I will take care of all those poor fellows but अर्टिफिसल प्राइस रखकर हमको चोर बना रहे हो, बदमाश बना रहे हो, एडल्ट्रेशन बढ़ा रहे हो। No american President has guts to charge Rs. 10 a gallon for petrol और यह जो वह कंडीशन डिफ्रेंट हैं। I have no time to go into that.

No American President has guts to charge Rs. 10 a gallon for petrol 11 have no time to go into that. प्रोपर प्राइस चार्ज कीजिए और यह सब ग़ड़बड बंद करिए । थैंक्यू सर। Thank you very much, Sir.

THE VICE- CHAIRMAN (SHRIUDAY PRATAP SINGH): The words, * and * will not go on record.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me an occasion to participate in this very important discussion and deliberation. I will speak only as long as you bear with me and as long as you think it is worthwhile. So, Sir, you can stop me whenever you feel like. I don't have very valuable suggestions to put forward nor am I an expert in this issue. I have no pretension to tell the Ministry how to improve things and what solutions to put in. But I realise one thing intensely and gravely that the issue which has been raised through this Resolution by Shri Vijay Darda is worth serious consideration and he has drawn attention to a very vital problem which is being faced throughout the country, and he has exposed in his Resolution the most vital facets of this problem in a very lucid manner. I want to congratulate, with your permission, Mr. Vice-Chairman, Sir, Shri Vijay Darda, for bringing out such a lucid exposition of his vital Resolution.

I agree with him that it is a matter of deep concern for the whole country, the village, town, city, every consumer that supply of crude oil, LPG and other petroleum products is not adequate and it is costly also. It hurts both ways. There is a paucity of LPG, and, along with scarcity, the element of cost is also there. I fully agree with him.that there is need for finding out some new sources, need for more exploration, need for new sources of energy also and need for controlling consumption as well. Shri Bajaj, a successful businessman, has just moved out after making his very interesting comments. Sir, the two things, which he has said are, I think, very proper and are very relevant to the issue. One is produce more, and, another is, consume less. A laymen will also say this and an expert will also say this. How to produce more is a very difficult thing. How to consume less can be understood to some extent — lesser numbr of vehicles, better public transport system and a kind of graded taxation for those who have more vehicles, luxury cars. In that graded value system, let there be more subsidy for those who use kerosene. The kerosene is used by the lowest segment, the poorest segment, the most deprived segment of the society who usually have no other source of kindling a light in their house. They don't have a candle, they don't have electricity, they don't have a generator, they have only a small *kuppy* of kerosene which is lighted when night comes up. So, for kerosene, there should be maximum subsidy, and, along with that maximum subsidy for kerosene, it must be ensured that it goes to the persons who deserve it, it goes to the real people for whom we wanted it to go. So, there has to be a more effective Public Distribution System for kerosene so that kerosene is not diverted for adulteration with diesel or petrol. Kerosene is vital. Next to kerosene, diesel is also vital for the nation because

*** Not recorded.**

diesel is the main input as far as energy is concerned for the farmers who constitute 70 per cent of India's population. It won't be an exaggeration to say that the heart of India still throbs in its villages. Village economy is dependent on agriculture and agriculture is not dependent on bullocks or camels now. It has become increasingly dependent on tractors or threshers that have come up as a mechanisation. Diesel is the input there. So, they must get the desired quantity of diesel. An agriculturist will never use diesel for the fun of it as a rich man uses it in his sports car. He uses only that much diesel which is necessary as an input for agriculture, in tractors or other mechanised instruments. Let him have an assured supply of diesel at the right time and at the right price. For him diesel has become as important as seeds or irrigation. Land without diesel or land without water or land without seeds is really fallow. So, diesel is an area of concern as far as the jurisdiction of the Petroleum Ministry is concerned.

After diesel, LPG is a common product in the towns and cities. LPG is not available in 80 per cent of the villages of the country; this figure could be more, it may even be 90 per cent. Villages don't have LPG. LPG is a concept of the urban areas. It is required more in the urban areas where we have become habituated to an easy way of cooking. *S<f,* LPG also has to be rightly subsidised. Everyone sitting here is a consumer of LPG; this is for sure. I hail from Jaipur, Rajasthan. I find that there are long queues; people don't get LPG for a month or two. There is shortage of LPG cylinders throughout the country; we cannot deny that. Here, on the floor of the House, I found the hon. Minister saying that there is no shortage of LPG but the fact is that there is, indeed, a shortage. Apart from shortage in LPG the other problem is that LPG cylinders weigh less. There is no transparency. LPG supply suffers from under-weight, diversion as well as corruption. In fact, in the urban areas, LPG has become a cesspool of corruption. There is no doubt about that. I think Mr. Darda has rightly said in his exposition, 'zero tolerance for any indulgence in corrupt practices or diversion of subsidised petroleum products to unintended beneficiaries'. I think, as far as punitive action is concerned, these two last lines of his resolution are very vital. Are we able to ensure that once we catch a culprit he is punished? He may be a petroleum dealer, he may be a diesel outlet dealer, he may be an LPG dealer, or he may be an official of any of the petroleum public sector undertakings. Once he is caught, let there be punishment for it. I do not have the figures but if statistics are brought out, you will find throughout the country, there must be seldom anyone who has ever been jailed for committing an offence under the LPG rules and regulations. Either we are tolerant or the people who execute the policies are corrupt. Both these things have been very rightly pointed out and more said, the better. It is really a cess pool of corruption. In fact, getting an LPG dealership is also usually, at tmes, either by corruption or by recommendation, rarely by fair, equitable method and on merit. It is a common experience and these connections also are *benami* most of the time. You will find petroleum outlets in the name of a *dalit,* in the name of an *adivasi,* in the name of a widow of a deceased war hero, but somebody else is operating and the real family by whose name it has been allotted hardly gets out of it. This is not the real issue on which I would like to talk, but this is one of the important issues. How to root out corruption in the total system of distribution of LPG crude oil and other petroleum products, and how to ensure transparency, fair and equitable distribution? These are very, very important things which need very great attention. If we are able to handle it, then, I think, most of the maladies will be over. How to control consumption? there is no easy solution to this. How to lessen the number of vehicles and how to increase more public transport system? It needs a more detailed study by some expert group to come to certain conclusions and those conclusions then should be put into

practice. Globalisation is a fact with which we have to live, no doubt about it, and about globalisation we should have the best possible latest innovative technology and not obsolete one, as has been very rightly pointed by Shri Vijay Darda. By opening our gates to outside big and international companies, 1 think, we will get better expertise. Rajasthan is one place where recently we have struck liquid gold in Barmer, which is being explored by Cairn, an international firm, but refinery is in doldrums. No decision has been taken whether the ONGC will take refinery or the Government of India will take some steps or not. But Rajasthan is looking forward with a ray of hope that there will be an equitable disposal of this issue by the Central Government. It is a very important thing for us. Barmer is the total desert area. It is such an area where water is more important than nectar. This liquid gold we have struck with God's grace. My appeal to the Central Ministry is to become kind-hearted to help Rajasthan in this matter. How to increase indigenous production? Can we have bio-diesel? Can jatropha cultivation in barren or desert land help us? Can ethanol be used as an alternative fuel? These are all matters which can be looked into by experts only. But there can be some bio-diesel element in the overall kitty. I feel that way. Regarding LPG one thing more should be there. Some method should be found out so that cylinders are pilferage-free. Regarding ghost ration cards, this comes within the purview of the States. States have to be more vigilant. I think, Sir, NGOs can come forward to clean this open stable of ghost ration cards, it is a truth that those who don't deserve it get the benefit because of the lethargy of the Government and because of our not being strict to apply rigid standards. I think, Sir, I have taken enough time. I won't exhaust your patience or exhaust my breath also. *(Interruptions)* But I won't speak for the sake of speaking. Whatever I thought was worth consideration, I have brought it to your kind notice, and, I am ever grateful to you for your kind indulgence, for giving me unlimited time. Thank you.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this issue. Sir, I find this particular discussion extremely important and interesting. I wish that the hon. Petroleum Minister were here but, I think, his very competent deputy, who is here, should be able to communicate all this to the Minister and also the whole Cabinet. J must say that Mr. Vijay Darda has really brought out certain very major problems of a sector like Petroleum that covers many different areas.

He has given you an opportunity to come out with a white paper or a policy statement on all the different elements that he has talked about. As Mr. Pilania also said, quite of them would require substantive expert studies but the questions are very relevant and they should be brought out clearly and answered clearly. Sir, I am happy that we have here Mr. Mani Shankar Aiyar, who, I think, was one of the best Petroleum Ministers in our country. I have been working for the Petroleum Ministry for many years. Sir, Mr. Chidambaram will admit that during the time of Gujral Government — Mr. Jaipal Reddy is also sitting here — there was a crisis for the petroleum prices because of the enormous amount of money debts accumulated to the public sector companies, and, I was asked to find a solution to this, and, if I may take a little pride in telling this, petroleum bonds were issued at that time which, to some extent, did support and help these companies. But there was a clear understanding that
after that markets will come to play, there will be no more subsidies except for LPG and kerosene. The Cabinet took this decision but, unfortunately, when the BJP or the NDA Government came to power, the particular promise was completely withdrawn and we again went to the same kind of problem. Sir, Mr. Mani Shankar, during his short tenure, raised certain basic issues in the petroleum sector, which, I am afraid the Government has still not tackled.

Sir, one of the most important points is that if we want to solve the problem of petroleum prices in our country, we must find methods of having greater supplies. It is not just a question of wheat or rice. It is a question of any major commodity, and, since the total supply in India is limited, we have to look for regular dependable supply sources all over the world. For the limited period Mr. Mani Shankar was there, he managed to make a number of breakthroughs that should have been followed very clearly by our Government. It is not only a question of Iran pipeline but in several countries, several areas, in Latin America, in Russia, in Africa also, he made the first forays of the Government of India getting into their business. That, unfortunately, has not been followed up systematically after that. I am mentioning all this because, I believe, this gives the Petroleum Ministry an opportunity to come back to this House, talking about each of the problems that Mr. Vijay Darda has raised. One is, procurement from outside the country. Second is, as he has pointed out, how to increase production within the country, exploration and more new technology. It is not at all clear as to what the Government is doing on this, especially since the technology of oil production has changed enormously, particularly with the Norwegians making major progress in this technology.

But, I would like to spend more time on something that is concerning everybody today and Mr. Natchiappan has raised this issue very clearly. It is the question of how to protect the consumers from this increasing price situation, inflationary situation, in the world. Sir, Mr. Rahul Bajaj has left. He made a number of points, of which, one major element of truth was that whatever consumption subsidies you provide, you must be sure that they do not affect production. How to organise our subsidy system or consumption price system so that production interests are fully taken care of? I must say, if he had listened to Mr. Natchiappan carefully, he would have found that in his propositions, he has touched upon many basic issues. Can we insulate the poorest of the poof from the rich? This is a problem for all essential products and, in this case, kerosene and LPG are essential products. This is a major
area of concern for the Government. Is it possible to have a nearly foolproof, not completely foolproof, system of identifying the poor and then seeing that the poor gets the actual support and the actual benefit? Mr. Bajaj is very right that if the poor can purchase and sell, you don't have to bother about it. There is a redistribution that takes place. But, still, we should try to protect the poor with a clearly identifiable method. That technology exists today. Sir, we have the system of smart card. We can provide that information. Now, because of the IT development, all throughout the country, these facilities of identification through smart cards exist. The only question is, it will have to be organised properly. Maybe, there will have to be at the Panchayat level, some kind of a monitoring system so that if I am a beneficiary of that card, my name should be openly declared. And if somebody says that I am not, then, that should be immediately enquired into. Some kind of monitoring should take place.' This is an essential element of any kind of pro-poor programme. Sir, I want to mention this' to the hon. Petroleum Minister that this is a case where he could set an example for almost all products, for which we have to give this kind of subsidy. What is the method of doing that? How to identify the poor? And, then protect them.

Now, having said that, the question remains, what happens to the prices? And, there, I fully agree with Mr. Bajaj. There is absolutely no justification for our not raising the prices of petrol and also diesel. It's not LPG and kerosene. Let me eleborate on this point a little bit because I think, some basic mistakes are being made in our policy decision. Unfortunately, my Left friends are also equally guilty of confusing issues because if you are not going to pass on the cost of inputs which has permanently increased to the ultimate users, then, the

economics of the market will see that you go bankrupt. This is the first point. The cost of permanent increase must be passed on to the final users. Then, the question comes, a question of judgement. You can protect only those who cannot afford. But, you cannot say that the entire 100 per cent people of the country cannot afford. If that is the situation, then we have already become bankrupt. The whole question is, among these people you choose the poorest of the poor whom you should protect through this kind of a smart card, through this kind of a special procedure, but for the rest, if you try to protect them, you will fail. What does it mean? It means—again, Mr. Bajaj put it in that way, what Mr. Natchiappan also said—you are protecting those who should not be protected by using public money, either through deficit financing or through taxes. The moment you do that, the question would be, what are the alternative uses of that public money? Should I protect a person who is running cars and spents on luxuries or should I use that money for hospitals or schools or other private benefits? Every resource has to be used. This choice has to ramain. I am saying that ultimately, this cost has to be passed on. You cannot say that you will not pass it on to the consumer. How you pass it on; that is a subject which you will have to carefully work out. I find it very sad to say that my Left friends are again and again 'saying that no increase in petrol price allowed! Now, what is the meaning of that? They are not here; Mr. Raja is also not here. But I have mentioned this thing to them again and again. 'You are talking about a fiscal system where you have no option, where you have no alternatives'. The same amount of money could do so many other things. So, Sir, what I am trying to put forward is that this is the time when we can think of working out a proper subsidy mechanism, identification of the poor who deserves and, then seeing that these smart cards are provided to them through a process that can be
monitored, and if there is a mistake, that can be corrected. If they are not corrected, you hold accountable the people who are involved and, then you enter into a programme for the country, as a whole, which can be defended.

Now, this is very important, Sir. I do not agree with Mr. Bajaj that there is no effect on prices. Actually, petroleum price-increase has a major effect on inflation because it is one input which gets into the outputs of many, many commodities. So if this input cost goes up, the output prices of many other commodities will also go up; it will have an effect on inflation. You can't help it. Then, prices are increasing because the cost of production is increasing, the cost of processing is increasing. That will have to be accommodated. So, the only thing that we can do is to manage it through a particular process of subsidisation. Sir, I would put it to you and, through you, to the Petroleum Minister, and, through the Petroleum Minister, to the Government, that please take this opportunity to work out a policy of protecting the poor people from essential commodity price-hike. We are living in a world where the prices go on increasing. This point of Mr. Chidambaram, I accept. The fact of the matter is that one effect of globalisation is that we cannot insulate ourselves from the world inflation, particularly when the world prices are higher than the domestic prices. Then, there will be leakages; there will be smuggling; there will be again and again interest in hoarding and smuggling, and selling it at a higher price. This is happening in our country. There is a huge border with Pakistan and Bangladesh, and even with Nepal; no one would be able to prevent goods from going away from India to other places if our prices are low. This is an international situation which you must accept, plus if you accept our modern banking system, then money will flow, capital will flow, and everything has now an international context. So, we shall not be able to arrest increase in prices. We only have to manage. And petroleum is the best example of a commodity which can be managed, and what you should do to manage them. So, this is my request, I think Mr. Darda should be complimented; he has brought out this thing in the

5.00 P.M.

open, and I hope that the Petroleum Ministry will respond to it, if no today, but over a period of time in the form of a Government resolution of how to accept, how to control this kind of a situation. Thank you very much. **श्री दिन्शा जे0 पटेल**: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय विजय जे0दर्डा जी ने एक महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया हैं जिस में बहुत सी बातें कहीं गयी हैं और दर्डा जी के साथ डा0 ई0एम0 सुदर्शन नाच्चीयप्पन जी, श्री राहुल बजाज, डा0 ज्ञान प्रकाश पिलानिया, श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

महोदय, मेरा पॉलिटिकल केरियर 36-37 साल का हैं। इस बीच मैं गुजरात राज्य विधान सभा में भी बहुत साल रहा और यहां भी 12 साल से हूं, मगर यह पहला मौका हैं चूंकि आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं हैं, इसलिए मुझे पहली दफा मौका मिला हैं और यह मौका अपर-हाउस में मिला हैं, इस कारण मुझे आज बहुत खुशी हो रही हैं। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यकत करता हूं, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया या जिन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया, मगर उन्होंने यह बात सुनी। उन सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, संकल्प में दर्डा जी ने मिलावट की बात कही हैं और उन्होंने एक कवि की भाषा में इस बारे में विचार प्रकट किए और मिलावट की बात शेयर की, इसमें मुझे ऐसा लगता हैं कि उन्होंने हमरा अपमान नहीं किया हैं, हमारा बहुमान किया हैं।

ऐसा मैं मानता हूं। उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का बहुमान किया हैं, ऐसा लग रहा हैं। उन्होंने मुंबई की बात कही और द्वारका हो जाएगी, ऐसी बात कही। तो दर्डा जी मैं कहता हूं कि अगर वह द्वारका हो जाएगी तो उसमें आपको क्या दिक्कत हैं? द्वारका तो कृष्ण भगवान का स्थान हैं। द्वारका की बात आप ने कही ...(**व्यवधान**)... द्वारका पांच दफा डूबी हैं, मगर आज द्वारका हैं और वह कृष्ण का स्थान हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसी मैं आपको गांरटी देता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, उन्होंने पेट्रोल पंप चैकिंग की बात कही हैं, सर, मैं कहना चाहता हूं कि करीब 33000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप्स (आर0ओ0एस0) सभी कंपनीज के सारे देश में हैं और इन आर0ओ0एस0 का चैंकिंग करने का काम भी हमारी कंपनीज हर दफा करती हैं। सर, उन्होंने उन 33000 में से जिनका 2007-08 (अप्रैल से दिसम्बर) में inspection किया हैं, उसमें 87528 टाइम्स अर्थात् करीब 3 टाइम्स उनका चैकिंग हुआ हैं, उसमें से 109 पंप्स का टर्मिनेशन हुआ हैं, उसमें से 1150 का फाइन किया गया हैं और 532 को नोटिस भी दिया गया हैं। सर, एक गाना हैं कि " चिट्ठी आई हैं" तो चिट्ठी आती हैं, किसी की चिट्ठी माननीय चैयरमेन से आती हैं तो सुनना भी पड़ता हैं और कोशिश भी करनी पड़ती हैं कि उसमें से कौनसा रास्ता निकाला जाए। तो चिट्ठी भी आती हैं, मगर जो सही बात हैं कि मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो मिलावट रोकने के बारे में सभी ने सोचा हैं। हमारे डिपार्टमेंत ने भी सोचा हैं और मार्कर सिस्टम के द्वारा उसमें मिलावट न हो, उसके लिए भी एक साल से पूरी कोशिश की जा रही हैं। सर, सभी पंप्स पर मार्कर चैकिंग कर इमीडिएट स्क्वैड के दारा भी रैंड कर के उसे कैसे पकड़ा जाए, वह काम भी चल रहा हैं। इसलिए मैं दर्डा जी को कहना चाहता हूं कि आपने जो भी बताया हैं वह बहुत अच्छी चीज हैं। सर, उन्होंने जो एलपीजी की रीफिल ऑडिट की बात की, तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004-05 में 6,400, 2005-06 में 14,177 2006-07 में 15878 चैकिंग हुई हैं और आगे भी हर दफा चैकिंग होंगी। जो एक्शन लिए गए हैं, वे वर्ष 2004-05 में 484,2005-06 में 517, 2006-07 में 357 और आगे अभी 333 मामलों में एक्शन लिए गए हैं। इसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन्स बनाए गए हैं कि अगर कभी कोई पहली चैकिंग में पकड़ा जाता हैं, तो उससे 20,000/- रुपए का फाइन लिया जाता है और जो एलपीजी की कीमत होती हैं वह कीमत भी वसूल की जाती हैं, दूसरी दफा अगर पकड़ा जाता हैं तो 50,000/- रुपये का फाइन और एलपीजी की कीमत वसूल की जाती हैं और तीसरी दफे पकड़ा जाता हैं उसका लाइसेंस कैन्सिल किया जाता हैं दर्डा जी, आप मेरी बात सुनेंगे। ...(**व्यवधान**)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (**श्री वी0 नारायणसामी**): दर्डा जी, आप यहां सुनेंगे।

श्री दिन्शा जे0 पटेल: तो एलपीजी के लिए यह प्रोविजन भी किया गया हैं। अभी जो लास्ट में एक माननीय सदस्य ने बात की, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास करीब 13 करोड़ एलपीजी की बोतल हैं, करीब 49 परसेंट लोगों को कवर

किया गया हैं और 9365 डीलर्स हैं। ये जो 13करोड़ बोतल हैं, इसमें करीब 10 करोड़ लोगों के पास यह कनेक्शन हैं, करीब 49 परसेंट लोगों को इसमें कवर किया गया हैं। मैं कहता हूं कि सारी दुनिया में कहीं भी ऐसा एलपीजी सप्लाई का नेटवर्क नहीं हैं। कहीं-कहीं दिक्कते आती हैं, जैषे कभी-कभी ट्रेफिक की प्रोब्लम होती हैं तो दिक्कत हो जाती हैं, कहीं अगर कंपनी में स्ट्राइक होती हैं तो दिक्कत हो जाती हैं, कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता हैं तो भी दिक्कत हो जाती हैं और कहीं ज्यादा बारिश आ गई तो भी दिक्कत हो जाती हैं। ति इसमेम सप्लाई में कभी –कभी शॉर्टिज आ जाती हैं ओर सप्लाई की शॉर्टिज से प्रोब्लम होती हैं। जहां तक बोतल का हैं, जैसा मैंने बताया कि 14.2 किलों की बोतल हैं वे डोमेस्टिक परपज के लिए हैं, जो घरेलू यूज की हैं। इसमें कोई गड़बडी न हो, इसमें कम गैस न हो, इसके लिए भी सभी तरह के प्रावधान किए गए हैं कि चैंक करके लेने का हैं कि बोतल का पूरा वजन हैं या नहीं, यानी नापने का प्रावधान भी किया हैं। जो 19 किलों की बोतल हैं, वे कॉमर्शियल बेस पर दी जाती हैं। इस कॉमर्शियल यूज में, यह जो 14.2 किलो की डोमेस्टिक यूज की बोतल हैं वह डायवर्ट ने हो, इसके लिए भी कोशिश की जाती हैं, मगर कहीं-कहीं होटल में, कहीं बेकरी में, कहीं रिक्शा में, कहीं कार में यह डायवर्ट होती हैं। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि यह डायवर्ट होती हैं, मगर पूरी कोशिश की जाती हैं कि कम से कम डायवर्सन हो। ...(**व्यवधान**)...

श्री वी0 नारायणसामी: तो इस डायवर्सन को ठीक करिए।

श्री दिन्शा जे0पटेल: सर, कोशिश होती हैं कि कम से कम गलत जगह जाए, कम से कम उसमें कोई गड़बडी हो, सभी लोगों के पास टाइम पर पहुंच जाए, सही वजन में पहुंच जाए। इसके बाद यह पांच किलो की भी डोमोस्टिक बोतल निकाली गई हैं। इसमें अभी तक संशोधन की बात यह चल रही कि पारदर्शी बोतल हो, जिसमें पूरी गैस हो और कोई भी ग्राहक उसे देख सके कि गैस उसमें पूरी हैं या नहीं हैं। इसके लिए भी कोशिश चल रही हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इथनोल की बात कही और ब्राजील की बात कही। पेट्रोल मे फाइव परसेंत इथनोल मिलाकर बेचने का काम यहां भी शुरू हो गया हैं। आगे उन्होंने बताया कि ब्राजील में करीब 80 परसेंट 100 परसेंट इथनोल से वाहन चलते हैं। मैं दर्डा जी को और मेरे साथी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इस देश में जो वाहन चलते हैं, उनमें करीब 70 परसेंट टू-व्हीलर्स वाहन हैं। 70 प्रतिशत लोग टू- व्हीलर्स यूज करते हैं, बाकी 30 प्रतिशत में थ्री-व्हीलर्स, फोर- व्हीलर्स, सिक्स-

बहुत कम करीब 33,34 मिलियन मीट्रिक टन ही आयल है, करीब 72 परसैट हमको बाहर से आयात करना पड़ता है। हमारे यहां करीब 19 रिफाइनरीज हैं, 17 रिफाइनरीज गवर्नमेंट की है, दो रिफाइनरीज प्राइवेट हैं – रिलायन्स और एस्सार । मगर, हम यहां से पैट्रोल बाहर भेज सकें और उससे पैसा कमा सकें, इस पर कैसे काम कर सकें, यह भी हम कोशिश कर रहे है। जितना ज्यादा पैट्रोल हम सकें,जितनी भी कोशिश हो सकती है, OVL के जरिए परदेस में भी हम कैसे आगे बढ सकें, वह भी हर जगह कोशिश कर रहे है।

मिट्टी के तेल की बात एक महत्वपूर्ण बात है। LPG के साथ जो गरीब लोगों के लिए बात की गई, बजाज साहब ने और कई अन्य सदस्यों ने इस पर बोलते हुए कहा कि पैसा बढा देना चाहिए,यह करना चाहिए वह करना चाहिए। मैं सभी सदस्यों से पूछ्ता हूं कि यह हाऊस यूनेनिमसली रेजोल्यूशन पास करें और लोक सभा भी यूनेनिमसली रेजोल्यूशन पास करके बोले और फिर लोगों के पास जाएं कि यह बढा हुआ है, यह ठीक है, वह बोलना पड़ेगा। अकेले खाली दिन्शा पटेल या मुरली देवरा बोलेंगे, तो कैसे चलेगा,वह नही चलने वाला है, लोग नही चलाएंगे। लोगों को केवल सस्ता चलता है, अगर एक रुपया भी पेट्रोल में बढता है, तो आज भी सारे देश में लोग चिल्ला रहे है कि एक रुपया पेट्रोल के दाम में बढने के कारण महंगाई बढ गई,दो रुपया डीजल में बढ़ने से सारे देश में बढ गई, और कोई कारण ही नही है, यही अकेला कारण है। तेल का जहां तक सवाल है, 25 डॉलर ,30डॉलर, 40डॉलर ,60डॉलर पर जो कीमत तय होती थी, आज वह 114 डॉलर प्रति बैरल है। मैं इस Upper House से यह कहना चाहता हूं कि 114 डॉलर प्रति बैरल की कीमत के बवजूद, आज सारी दुनिया में 9 रुपए,पांच पैसे प्रति लीटर की कीमत पर मिट्टी का तेल भारत के सिवाय कही नहीं दिया जा रहा है। हमारी UPA सरकार ने यह तय किया है कि वह गरीबों को सस्ती कीमत पर ये चीजें उपलब्ध कराएगी। अब PDS में गड़बडी होती है, वे बेच देते है। उनको भी 5-10-15 रुपया मिलता है, तो वे केरोसिन बेच देते है, मैं इसे जानता हूं और हम इसे रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं,लेकिन जो दो नंबर में खरीद सकते है, उसको बचाने के लिए क्यों हम लोग चिट्ठी लिखते है, यह भी सोचना पड़ेगा। वे लोग किसके पास जाते है?

श्री विजय जे.दर्डा : आपके पास ऐसे कितने दो नंबर वाले लोगों की सूची है, जिन्होंने ये पत्र लिखें है?

श्री दिन्शा जे.पटेल : किसी ने पत्र लिखा है, ऐसी बात मैंने नही कही है, कभी –कभी हमें बोलते है कि ये देख लेना, यह जरा देखने की बात है, तो देखना पड़ता है। अब केरोसिन का डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, यह उन्होंने करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां की स्टेट की मांग के अनुसार,उसके सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को केरोसिन देती है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन वह सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट करता है और जो भी ऐक्श्न लेना है, इसके लिए भी सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को पावर्स दी गई हैं। अगर स्टेट्स इसे अच्छे तरह करेंगे, तो अचछा काम हो जाएगा। मैं सभी स्टेट्स से अपील करता हूं कि वे लोग इसमें साथ दें, ताकि गरीब लोगों तक ये चीजें पहूंच सकें, ऐसी कोशिश सभी को करनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सद्स्यों ने बहूत सी बातें कही है, उन्होंने बहुत से प्वाइंट्स उठाए है, और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल देश के लिए ही नहीं, बलिक सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण विषय में सभी मेंबर्स ने interest लिया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। श्री विजय दर्डा जी यह संकल्प लाए है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यावाद देता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो PDS का केरोसिन 9 रुपए , 5 पैसे प्रति लिटर की कीमत पर मिल रहा है, यह पूरी दुनिया में सबसे सस्ता केरोसिन है, हमारे पड़ोसी देश में भी इतनी सस्ती कीमत पर नहीं मिलता है। इस प्रकार यह सरकार कोशिश कर रही है कि यह केरोसिन गरीब लोगों को मिले। अब माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि पैसे वालों के ऊपर डाल दो, अब कैसे डाला है, यह भी बताया । अब पैसे वाले सहन करेंगे या नही करेंगे, पता नही । मैं पूछता हूं कि इसके लिए बोलने वाले कौन है? जो पढ़े-लिखे लोग है, वो बोलते है, आज पढ़ॅ –लिखे जो बात कर रहे है कि महंगाई है , महंगाई है , महंगाई है और जो बेचारा गरीब है, एक झोंपडी में रहने वाला है, वह कभी भी नही बोलता है वह कभी नही बोलेगा कि महंगाई हैं। वह बेचारा तो रोटी मिल गई, तो ठीक है,नही मिली,तो दोपहर को मिलेगी, दोपहर को नही मिली, तो शाम को मिलेगी, ऐसा सोच रहा है। बोलता कौन है? जो पढ़ा –लिखा है,वह बोलता है,जो व्यापारी है, वह बोलता है, जो इंड्स्ट्रीज वाला है, वह बोलता है, जिसके पेट्रोल पंप की चैकिंग होती है, वह बोलता है, जिसकी गैस एजेंसी की चैकिंग होती है जिसके पेट्रोल पंप की चैकिंग होती है, वह बोलता है, जिसकी गैस एजेंसी की चैकिंग होती है, लेकिन दूसरे लोग नहीं बोलते है। इसलिए सभी लोगों को इसमें साथ देना चाहिए, सभी लोग साथ देंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दर्डा जी से यही कहना चाहता हूं कि आपने जो कवि की बात कही थी, मैं भी आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। मै सभी को कहना चाहता हूं-

"लगा सको, तो बाग लगाना"

मगर बाग कहां लगाना है, किसी गरीब किसान के खेत में बाग लगाना है, कि किसी गरीब की झोंपडी में बाग लगाना है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बच्चा पढ़ सके , इसलिए बाग लगाना है। कोई छोटे से गांव में पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके यहां बाग लगाना है। गरीबी हटाने के लिए बाग लगाना है।

" लगा सको, तो बाग लगाना,

आग लगाना मत सीखो।

जला सको, तो दीप जलाना...."

कहां जलाना है दीप? गरीब के दिल में दीप जलाना है, किसी किसान के घर में दीप जलाना है, किसी बुढ़िया विधवा के घर में दीप जलाना है। हमें इस देश के सारे घरों में दीप जलाना है, तो कैसे जलाएंगे?

"जला सको, तो दीप जलाना,

दिल जलाना मत सीखो।"

लेकिन यहां तो दिल जलाने की बात हो रही है। मैं वहीं कहना चाहता हूं कि

"लगा सको , तो बाग लगाना,

आग लगाना मत सीखो।

जला सको,तो दीप जलाना,

दिल जलाना मत सीखो।"

अगर यह बात सभी लोग सोचेंगे, तो मैं मानता हूं कि हम जो रोशनी करने की बात सोचते हैं, अभी आजादी की बात की गई ,सुदर्शन जी ने आजादी की बात की, तो मैं भी उन्ही घरों में से आता हूं। मै भी किसान का बेटा हूं,किसान का लड़का हूं, मेरे बाद-दादा और बाकी लोग जेल गए है पांच-पांच के लिए। आज भी मेरी 103year old mother-in-lawमेरे यहां है। वे पांच साल निरौला जेल में कस्तूरबा के साथ थी। मेरा नेटिव वहीं है जहां सरदार पटेल का बर्थ हुआ हैं, Nadiad और यहीं नहीं है,जहां बर्थ –प्लेस है,उसी मिट्टी में खेलकर मैं आया हूं, इसलिए मेरे दिल में भी वह जलन है कि सभी का काम होना चाहिए,छोटे-मोटे की बात छोड़नी चाहिए, सभी का काम हो और सही दिशा का काम हो, सच्चा काम किसी का भी हो, वह होना चाहिए-यह सही बात दर्डा जी ने बताई है, सभी साथियों ने बताई है और उसके साथ मैं जुड़ता हूं, लेकिन सभी का साथ होगा, तभी जो कुछ करना है, हम वह कर सकेंगे। बहुत सी बातें मैं माननीय वाईस चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं ,दर्डा जी से भी वही बात पूछना चाहता हूं कि मेरा जो स्टेटमेंट है, वह करीब बीस पेज का है। आप आज्ञा दें,तो मैं उसको पढ़ दूं? यदि आप कहें, तो मैं सभी सदस्यों को उसकी एक-एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में भेज दूंगा और आपकी आज्ञा हो तो , यहां मैं उसे सभा के पटल पर lay कर देता हूं? कि वे अपने इस संकल्प को वापस ले लें और आप सभी का फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : आप जो जवाब दे रहे है, उसमें layकरने की प्रथा नहीं है। संक्षेप में तो आपने कह ही दिया है, धन्यवाद।

श्री विजय जे.दर्डा : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिन बिंदुओं पर मैंने प्रशन उठाए थे, उनका समाधान करने का यशस्य प्रयत्न किया है और साथ में दिल जलाने और बाग लगाने की बात भी कही है। वह बात भी उन्होंने उनके सामने कही, जो कि स्वयं एक बहुत बड़े कवि हैं, जो पीठासीन हैं। मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य से पूरी तरह से सहमत नही हूं। उन्होंने जो बातें कही है और जो प्रश्न मैंने उपस्थित किए है, उन प्रश्नों को नहीं छुआ है। आपने कबूल किया है कि मिलावट हो रही है। आपने यह भी कबूल किया कि गरीब किसान, गरीब व्यक्ति, आम आदमी परेशान है। आपने यह भी कबूल किया कि पीडीएस के माध्य्म से लोगों तक, सही लोगों तक- चाहे वह केरोसिन हो,चाहे गैस हो-नहीं पहुंच रही है। जवाब्देही चाहे राज्य सरकार की हो या केन्द्र सरकार की हो किन्तु सत्य यह है कि आम आदमी , जिसके लिए हमने टैक्स पेयर को, करदाता को टैक्स लगाया है , ताकि वह उन तक पहुंच रहा है। मिलावट में गिरावट आयी है। उस गिरावट के माध्यम से मिलावट को लेकर मैंने प्रदुषण की बात कही है। द्वारका से , मुम्बई से मेरा अर्थ यह था कि जो प्रदुषण बढ़ रहा है, उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी चिंता जतायी है, चेतावनी दी है। मैंने सरकार से अपेक्षा की थी कि कच्चे तेल और गैस के खनन में अधिक से अधिक वृद्धि हो। जहां कही भी हमारे ऑयल पीएसयूज सहभागी है, वहां से हमें निशिचत मात्रा और निशिचत मूल्य पर कच्चा तेल और गैस मिले। नयी तकनीक का सही तथा अधिकाधिक प्रयोग हो। शोध कार्य के लिए सरकार प्रयत्न करे। आल्ट्रनेट फ्यूल के बारे में निशिचत नीति हो। गैस की सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर के बीच में जो कडी बनी है, जिससे घरेलू प्रयोग वाली गैस व्यावसायिक प्रयोग के लिए ट्रांसफर हो रही है, वह रुके तथा तेल कम्पनियों का आचरण पारदर्शी हो। इन सब चीजों को लेकर ..(व्यधान).. मंत्री जी, आप मुझे समाप्त करने के लिए कह रहे है। मैं वही बात कर रहा हूं कि सब चीजें खत्म करिए ताकि आम आदमी का जीवन सुखद हो। मैं जानता हूं कि आप हार्डकोर फार्मर है , किसान है, किन्तु जेट्रोफा की बात, जिनको हम देश के सबसे बड़े विज्ञानविद कहते है, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम साहब ने भी यह बात कही है कि हमारे पास जितनी एग्रीकल्चरल लैंड है,उससे 6गुणा हमारे पास वेस्ट लैंड है। अगर उस वेस्ट लैंड का हम लोग जेट्रोफा के लिए उपयोग करें।

श्री दिन्शा जे.पटेल : जो मैं पेपर्स दे रहा हूं, सब कुछ उनमें हैं।

श्री विजय जे.दर्डा : सर, मैं एक शेर अर्ज करता हूं। इन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैं बोलना चाहता हूं सब कुछ उन कगजों में हैं।

सब कुछ है मेरे दिल में, फिर भी कयामत की निगाहें है।
बैठा हूं अपनी कुर्सी पर, फिर भी औरों का घर जला है।

कभी इधर,कभी उधर देखता हूं मैं।
पता नही, क्यों मैं खामोश हूं।

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके अंदर तो सब कुछ है। आप अपने डिपार्टमेंट से पूछिए। मैं कहना चाहता हूं कि वही रेल डिपार्टमेंट था, वही लोग थे, लेकिन जिस प्रकार से लालू जी ने उस रेल डिपार्टमेंट को बदला, उसी प्रकार से आपके पास भी सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद उसको बदलने की चेष्टा होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बातों को अधिक गंभीरता से लिया जाता है ओर उसका निदान निकाला जाता, उसके बारे में आप कोई जवाब दे देते, तो मुझे बहुत खुशी होती। मैंने जो-जो प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों का आपने अपने ढंग से जवाब दिया है, लेकिन मेरे कई प्रश्नों का समाधान नही हुआ है। जो बात मैंने कही थी, उसका जवाब आपने नही दिया है। मैंने आपसे कहा था कि चिराग हर एक घर के लिए ,कहां चिराग मयस्स्र नही शहर के लिए। उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं चाहुंगा कि मैंने जितनी बातें रखी है और विशेष रूप से आल्ट्रेशन वाला जो मामला है, उसकी ओर बहुत गंभीरता से देखने की आवस्यकता है, नई रिसर्च पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कीमत बढ़ जाती है तो उसका असर हमारी इकोनॉमी पर आता है। इसलिए इस कारण इसके अंदर रोक लगने में बडी मदद होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, पेट्रोलियम पदार्थों की ऊंची कीमतें हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत खोजने के लिए विवश कर रही है। जैसा कि मैंने आपसे ब्राजील के बारे में बात की थी कि उन्होंने आल्टरनेट फ्यूल को ढूंढ निकाला है और 1973 से

उसका यूज कर रहे है। उसी प्रकार से हमारे यहां भी होना चाहिए। इस दृष्टि से आप क्या प्रयत्न कर रहे है, वह बतलाने का प्रयास करें। मैंने जो दो-तीन बातें आपके सामने रखी है, यदि उनके बारे में मुझे जानकारी देंगे तो मुझे बडी खुशी होगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Mr. Darda, are you with drawing the Resolution?

SHRI VIJAY J. DARDA: Before I withdraw, I want to seek a clarification from the Minister on this issue.

श्री दिन्शा जे.पटेल : सर, श्री दर्डा जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया है उसका जवाब मैंने संक्षेप देने का प्रयास किया है। मेरा जो स्टेटमेंट है,उसमें आप सभी के द्वारा उठाई गई प्रोब्लम्स का जवाब है। उसके आगे भी मैं दर्डा जी को बोलता हूं.

डा0 ज्ञाण प्रकाश पिलानिया : अगर आपके स्टेटमेंट में है तो बताएं कि राजस्थान रिफाइनरी के बारे में आपने क्या डिसीजन लिया है ? क्या यह आपके स्टेटमेंट में है?

श्री दिन्शा जे.पटेल : राजस्थान की रिफाइनरी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि उसके लिए भी कोशिश चल रही है कि वह बाएबल या नहीं, वह वाएबल होगा या नही, उसके बारे में भी राजस्थान सरकार के साथ यह डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है , उसके साथ बात भी चल रही है। क्योंकि इतना बड़ा इंवेस्टमेंट करके फिर बाएवल न हो, जिसके बाद में दिक्क्त न हो जाए , वह भी बात चल रही है।

डा0 ज्ञाण प्रकाश पिलानिया : यह जो बात चल रही है कितने अरसे से चल रही है, एक साल , कोई लिमिट तो होगी?

श्री दिन्शा जे. पटेल : राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि इसमें इंवेस्टमेंट करना है और पंद्रह साल तक तेरह सौ करोड़ का हर साल व्य होना है। इसमें बहुत बडी कीमत लगनी है , इसलिए उनसे बात कर रहे है।
डा.ज्ञान प्रकाश पिलानिया : दर्डा साहब ठीक कह रहे है,He has backed out on many questions,

Mr.Vice-Chairman: Sir. He has not given straight replies. He has been evasive in his replies.

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: It would be better if you give the answer which has been laid because we don't know what reply you have given. Why don't you elaborate your reply?

श्री दिन्शा जे.पटेल : इसलिए मैं सभी को भेज दूंगा। मैं हिंदी और इंगलिश दोनें में भेज दूंगा। उसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हम देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दर्डा साहब को बोला कि यह बहूत बडा संकल्प है। यह हाउस के लिए ही नही सारे देश के लिए इंपोर्टेंट संकल्प है। यह बहुत काम का संकल्प है, बहुत जरूरी है और इसलिए आया है जिसकी मुझे भी खुशी होती है। मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यह संकल्प आप वापिस ले लें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Mr. Darda, are you withdrawing the Resolution?

SHRI VIJAY J. DARDA: Before I withdraw I want co seek two clarifications again. नई टैकनीक और हमारी क्षमता..(व्वधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : वे यह कह रहे है कि सब बातों का जवाब उनके स्टेटमेंट में है, जो वे भेज रहे है।

श्री विजय जे .दर्डा : वे बाद में भेजेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें तो वे यहां बतला सकते है। जो ओएनजीसी की गलत प्लानिंग की वजह से, ठीक समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण, दूर-दृष्टि के अभाव और सतत निगरानी के अभाव से, इस विभाग को निशिचित 2442 करोड़ रुपये के बजाय 3286 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े इसके बारे में आपका क्या कहना है?

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : दर्डा जी, उनके पास जितना जबाव था, वह सब दे चुके है।..(व्यधान)... दर्डा जी, आप बताइये कि क्या आप इसको विदड्रा कर रहे हैं?

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) : सर, हाउस की ऐसी परम्परा नही है कि वन दू वन क्वेश्चन –आन्सर हों।उन्होंने अपना इश्यू रेज कर दिया , मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : मैं उनसे यही कह रहा हूं।

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, the hon. Member moved his Resolution and the hon. Minister has given his reply. If he still wants to insist on his Resolution, it can be put to vote.

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : टेबल पर भी ले करने की परम्परा नही है, जब उन्होंने जबाव दे दिया है।

SHRI VIJAY J. DARDA: Yes, I am withdrawing. But, before withdrawal, I would like to say someting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): No, No, Either you withdraw it or insist for voting. You cannot continue like this.

SHRI VIJAY J. DARDA: I withdraw my Resolution. And while withdrawing, सर, सर्वप्रथम मैं इस सदन का धन्यावाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिसके समकक्ष मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव प्रस्तूत करने का अवसर प्राप्त हुआ । साथ ही प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का तथा समर्थन के लिए मैं माननीय सांसदों का भी धन्यावाद व्यक्त करना चाहूंगा । मैं विशेष रूप से डा.ई.एम.सुदर्शन नाच्चीयप्पन, श्री राहुल बजाज ,डा.ज्ञान प्रकाश पिलानिया,श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त का आभार व्यक्त करना चाहुंगा और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस बात को सुना , उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहुंगा।तेल के तमाम उत्खनन से लेकर नई तकनीकी के इस्तेमाल ,मिलावट, गैस की कमी और उसके उत्पादन संबंधी पहलुओं पर मंत्री जी ने जो आश्वासन दिए है, उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहुंगा कि कहीं ये आश्वासन फाइलों में दबकर नही रह जायें । 'न नौ मन तेल होगा , न राधा नाचेगी ' वाली कहावत चरितार्थ न हो । इसके साथ ही मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

Thee *Resolution, by leave, withdrawn*

Concern over the seting up of a number of special economic zones in the country

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, with your permission, I move:

"This House expresses its serious concern over the setting up of a number of Special Economic Zones in the country thereby depriving the farmers and agricultural workers of their fertile land and livelihood and leading to benefits to big business houses, who are geting various exemptions, including labour laws and tax exemptions, etc., despite the unanimous despite the unanimous recommendations of the Department-related parliamentary Standing Committee on Commerce against this and urges upon the Government to drastically amend the Special Economic Zones Act and rules making, all the laws to the land applicable in Special Economic Zones, and withdrawing all tax concessions to industries being set up therein".

Sir, this is for the first time that I rise the move a Private member's Resolution. This is a very small resolution, But, in my opinion, it is a very important Resolution. This Resolution is on the special Economic Zones.

In fact, in the month of March, I had a Starred Question on the very same subject, the entire was in uproar. Cutting across the political lines, hon. Members spoke on this and they